Regularisation of Muster Roll Workers in CPWD

1172. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Director General Works, C.P.W.D. have issued instructions to the effect that regularisation of muster roll workers should be done after preparation of panels on the basis of seniority-cum-fitness;

(b) if so, whether the coordination officers in Delhi have prepared and circulated such panels of muster roll workers for regularisation of Beldars, Khallasis, Malis, Chowkidars, Sweepers and Sewermen; and

(c) if not, what steps are being taken for proper regularisation of muster roll workers of these categories after preparation of such panels?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Coordination Officers have taken in hand the work of preparing such panels in respect of the categories of Beldars, Khallasis and Malis. The number of workers to be regularised will depend upon the Vacancies available from time to time. There are no muster roll workers in the categories of Chowkidars, Sweepers and Sewerman.

CPWD Staff Quarters at Dehradun

1173. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are CPWD staff quarters at Dehradun;

(b) if so, what is the number thereof; category-wise;

(c) whether these quarters are being allotted to both regular and workcharged staff working in Dehradun on the basis of combined seniority lists for each type of quarters; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दिल्ली विकास प्राधिकरण की हायर परचेज प्रणाली का समाप्त किया जाना

1174. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुडको योजना 1979 के अधीन पंजीकृत एल.आई.जी. और एम.आई.जी. फ्लैटों के आवंटितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हायर परचेज आधार की बजाय नकद भुगतान करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पूरा भुगतान करने में 15 या 30 दिनों के विलम्ब के लिए कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों को 12 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान करने को कहा गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण उपर लिखित लोगों को पूरा भुगतान करने के बाद भी तुरन्त फ्लैटों का कब्जा नहीं देता यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण आवंटितियों को क्वार्टरों का कब्जा देने तक उनकी जमा राशियों पर किस दर से ब्याज अदा करता है ; और

(घ) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हीं दरों पर ब्याज का भुगतान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिन दरों पर यह आवंटितियों से ब्याज वसूल करता है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केवल मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के आवंटियों को नकद आधार पर भुगतान करने के लिए कहा गया था। निम्न आय वर्ग के लिए भुगतान हेतु 50 प्रतिशत नकद तथा 50 प्रतिशत किराया-खरीद आधार रखा गया है ।